भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2681

11 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाएं

2681. श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों विशेषकर दादरा और नगर हवेली में कार्यान्वित की जा रही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत दो वर्षों के दौरान देश में विशेषकर दादरा और नगर हवेली में उक्त योजनाओं से लाभान्वित होने वाले तथा अपना रोजगार शुरू करने में सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं, की संख्या का राज्य-वार एवं जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजनाओं को समुचित रूप से लागू करने और उन्हें ग्रामीण लोगों के लिए सुलभ बनाने हेतु उठाए जाने वाले सकारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है ताकि सभी लोगों को लाभ मिल सके; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय अपने तीन विभागों; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) के माध्यम से देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष (एसटीआई) पारितंत्र को मजबूत करने की दिशा में विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। सभी योजनाएं अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वित की जाती हैं तथा किसी विशेष राज्य तक सीमित नहीं होती हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तीन छत्र योजनाओं को, (i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण, (ii) अनुसंधान और विकास और (iii) नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन और दो राष्ट्रीय मिशनों को, (i) राष्ट्रीय एकाधिक ज्ञान शाखागत साइबर भौतिक प्रणाली मिशन (एनएम-आईसीपीएस) और (ii) राष्ट्रीय क्वांटम (एनक्यूएम) मिशन क्रियान्वित कर रहा है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग 'जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवोन्मेष और उद्यमिता विकास (बायो-राइड)' योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसके तीन व्यापक घटक हैं: (i) जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास; (ii) औद्योगिक और

उद्यमिता विकास और (iii) जैव विनिर्माण और बायोफाउंड्री। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग अपने प्रमुख कार्यक्रम अर्थात "औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम (आईआरडीपीपी)" के माध्यम से उद्योग और संस्थान विनिर्दिष्ट प्रेरक उपायों और प्रोत्साहनों द्वारा देश में औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है, जिससे नवीन प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के विकास और उपयोग हेतु सक्षम वातावरण का निर्माण हो रहा है। हाल ही में प्रारंभ किए गए अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) ने अग्रलिखित कार्यक्रमों के समावेशिता अनुसंधान अनुदान (आईआरजी), उच्च प्रभाव क्षेत्रों में उन्नति मिशन (एमएएचए): ईवी-मिशन, त्वरित नवोन्मेष और अनुसंधान साझेदारी (पीएआईआर) और प्रधानमंत्री प्रारंभिक कैरियर अनुसंधान अनुदान (पीएमईसीआरजी) कार्यान्वयन की शुरुआत की है। इन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न घटक विभिन्न स्तरों पर फेलोशिप के माध्यम से मानव क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने, शैक्षणिक संस्थानों में सुसज्जित अनुसंधान एवं विकास उपकरण सुविधाओं की स्थापना के माध्यम से संस्थागत क्षमता का निर्माण करने, बुनियादी और अंतरणीय अनुसंधान सहित विभिन्न विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से सहयोगी अनुसंधान को बढ़ावा देने, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और उद्यमिता को सहायित करने में योगदान करते हैं। ये योजनाएं विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और गणित (एसटीईएम) में लैंगिक समानता लाने, समाज के अपहित वाले वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु प्रौद्योगिकी साधनों का प्रगत निर्माण करने आदि में महिलाओं की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती हैं।

(ख) सभी योजनाओं को देशभर में शोधकर्ताओं और संस्थानों को समान अवसर प्रदान करने वाले प्रतिस्पर्धी तरीके से लागू किया जाता है। तदनुसार, इन योजनाओं के लाभार्थी पूरे देश फैले हुए हैं। दादरा और नगर हवेली में ऐसा कोई ज्ञात लाभार्थी विशेष रूप से महिला नहीं है जिसे अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने में सहायता प्राप्त हुई।

(ग) से (घ): विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सभी प्रकार की वित्तीय सहायता के आवेदन/अनुसंधान प्रस्ताव ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं, जो देश भर के सभी शोधकर्ताओं/संस्थानों के लिए सुलभ हैं। ऐसे आह्वानों का मंत्रालय के वेब पोर्टलों और सोशल मीडिया हैंडलों के माध्यम से पर्याप्त प्रचार किया जाता है ताकि योजना का लाभ देशभर में लोगों तक पहुंच सके।

*****